



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 श्रावण, 1942 (श०)

संख्या- 371 राँची, शुक्रवार,

14 अगस्त, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

29 जून, 2020

संख्या-03/नि0सं0-09-41/2016 का. 3016-- माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा WP(S) 3915/2019, प्रेम रंजन बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 28.05.2020 को पारित न्यायादेश का मुख्य अंश निम्नवत् है:-

"13.From the aforesaid discussions and from perusal of documents and by carefully examining the rival submission of the parties and from perusal of entire records, I hold that the enquiry conducted against the petitioner was improper and in violation of the principles of natural justice. Since petitioner has already been considered for promotion but a sealed cover procedure has been adopted, I hereby direct the respondents to open the seal cover and consider case of the petitioner for promotion, if he is otherwise found eligible and there be no other legal impediment, within a period of eight weeks from the date of receipt/production of a copy of this order.

14. As a sequel of the aforesaid rules, guidelines, legal proposition and judicial pronouncement, I hereby quash and set aside the impugned order of punishment of Censure issued vide Memo No-287 dated 12.01.2016 as also the appellate order issued vide Memo No-8017 dated 16.09.2016 and further direct the respondents to pay admissible consequential benefits to the petitioner on being found eligible etc., in accordance with law.

This writ petition is accordingly allowed with aforesaid order and direction."

2. उक्त न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में उल्लेखनीय है कि श्री रंजन की अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु सर्वप्रथम दिनांक 04.01.2016 को सम्पन्न प्रोन्नति समिति की बैठक में विचार किया गया था तथा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित रहने के निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफा में रखने की अनुशंसा की गई थी।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप विभागीय संकल्प सं0 287, दिनांक 12.01.2016 के द्वारा श्री रंजन को निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया था।

4. WP(S) 3915/2019, प्रेम रंजन बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 28.05.2020 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय संकल्प सं0 2914 दिनांक 18.06.2020 के द्वारा श्री रंजन के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं0 287 दिनांक 12.01.2016 द्वारा निर्गत दण्डादेश तथा विभागीय संकल्प सं0 8017 दिनांक 16.09.2016 द्वारा अपील अभ्यावेदन अस्वीकृति संबंधी निर्गत आदेश को रद्द किया गया है।

5. दण्डादेश को निरस्त किये जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प सं0 6227 दिनांक 20.11.2008 के प्रावधानों के आलोक में श्री प्रेम रंजन, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक 834/03) के संबंध में दिनांक 04.01.2016 को समिति द्वारा अनुशंसित मुहरबंद लिफाफा को खोला गया, जिसमें समिति द्वारा “प्रोन्नति के योग्य” की अनुशंसा की गई है।

6. दिनांक 04.01.2016 को विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा अनुशंसित पदाधिकारियों को विभागीय अधिसूचना सं0 231 दिनांक 11.01.2016 द्वारा अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई है। श्री रंजन से कनीय श्री सुधीर कुमार गुप्ता (कोटि क्रमांक 835/03) को भी उक्त अधिसूचना के द्वारा अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई है।

7. अतः वर्णित तथ्यों की सम्यकरूपेण समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0 6227 दिनांक 20.11.2008 के प्रावधानों के आलोक में श्री प्रेम रंजन, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक 834/03) को उनके कनीय को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रदान की गई प्रोन्नति की तिथि 11.01.2016 के भूतलक्षी प्रभाव से अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

8. श्री रंजन को उक्त प्रोन्नति का वास्तविक वित्तीय लाभ प्रोन्नत पद पर पदस्थापन के उपरांत प्रभार ग्रहण की तिथि से देय होगा।

9. यह प्रोन्नति याचिका संख्या W.P.(S) No 3795/2003 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।
